

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

# CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



24<sup>th</sup> October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS  
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi



## INDEX

### DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

24<sup>th</sup> October 2022

1. - भारत-सऊदी अरब संबंध:.....	3
(i) इतिहास:.....	3
(ii) सऊदी अरब और भारत के बीच सामरिक भागीदारी परिषद क्या है? .....	3
(iii) आगे बढ़ने का रास्ता:.....	4
2. - बैंकिंग विनियमन अधिनियम:.....	5
(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का वास्तव में क्या अर्थ है? .....	5
(ii) अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं: .....	5
(iii) 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम को संशोधित किया गया है:.....	5
3. - 5 जी .....	6
(i) के बारे में: .....	6
(ii) ग्लोब इस समय किस राज्य में है?.....	6
(iii) क्या भारत 5G पर स्विच करने में सक्षम है? .....	6
(iv) 5G के निम्नलिखित लाभ भारत के लिए उपलब्ध हैं:.....	6
(v) 5G की शुरुआत के साथ मुद्दे:.....	7
(vi) आगे बढ़ना:.....	7



<b>4. - एनजीटी:</b> .....	<b>8</b>
(i) एनजीटी के बारे में:.....	8
(ii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है: .....	8
(iii) निम्नलिखित दीवानी मामलों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा नियंत्रित किया जाता है:.....	8
(iv) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:.....	8

<b>संपादकीय विश्लेषण</b> .....	<b>10</b>
--------------------------------	-----------

<b>1. तटीय कटाव:</b> .....	<b>10</b>
(i) पार्श्वभूमि: .....	10
(ii) तटीय कटाव को रोकने का क्या महत्व है: .....	10
(iii) तटीय कटाव के कारण: .....	10
(iv) भारत में तटीय कटाव की स्थिति: .....	11
(v) दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तटीय क्षरण:.....	11
(vi) पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट किस तेजी से खराब हुआ: .....	11
(vii) तटीय कटाव के प्रभावों में शामिल हैं:.....	12
(viii) तटीय कटाव को रोकने के उपाय:.....	12
(ix) स्थानांतरण: .....	13
(x) निष्कर्ष:.....	13

<b>2. सभ्यताओं का संघर्ष:</b> .....	<b>14</b>
-------------------------------------	-----------



## 1. - भारत-सऊदी अरब संबंध:

जवाहरलाल नेहरू ने राज्य का दौरा किया, जबकि राजा सऊद ने 1955 में भारत का दौरा किया।

### GS II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

सऊदी अरब और भारत के बीच सामरिक भागीदारी परिषद क्या है?

#### ➤ संदर्भ:

- नवंबर के मध्य में इंडोनेशिया के अपने मार्ग पर, सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधान मंत्री, मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस), प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत में रुकने की संभावना है। दोनों प्रधानमंत्रियों के 14 नवंबर को अपनी संक्षिप्त यात्रा के बाद बाली के लिए रवाना होने की संभावना है, जहां जी-20 की बैठक 15 से 16 नवंबर तक होगी।

- अक्टूबर 2019 में भारतीय प्रधान मंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के जवाब में, रणनीतिक साझेदारी परिषद बनाई गई थी।

ये इसके दो प्राथमिक स्तंभ हैं:

#### इतिहास:

- प्राचीन भारत और अरब के बीच पहला व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास बना था।
- वर्ष 1000 ई. तक अरब की अर्थव्यवस्था अरब और दक्षिणी भारत के बीच फलते-फूलते व्यापारिक संबंधों पर आधारित थी।
- यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के उदय से पहले भारत और यूरोप के बीच मसाला व्यापार पर अरब व्यापारियों का कड़ा नियंत्रण था।
- भारत तीसरे सऊदी राज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था।
- 1947 में दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद, दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्राओं का आदान-प्रदान किया। 1956 में प्रधान मंत्री

- राजनीति, सुरक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति पर समिति
- निवेश और अर्थव्यवस्था पर समिति
- यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने इस तरह की रणनीतिक साझेदारी विकसित की है।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध:

- सऊदी अरब, जो भारत की कच्चे तेल की 18% से अधिक की आपूर्ति करता है, चीन, अमेरिका और जापान के बाद देश का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- इराक पहले भारत का कच्चे तेल का मुख्य स्रोत था; सऊदी अरब अब उस पद को भरता है।
- सऊदी अरब भारत को बहुत सारा एलपीजी निर्यात करता है।



## सऊदी अरब और भारत में सांस्कृतिक समानताएं हैं:

- 2021 में योग सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, भारत में सऊदी खेल मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने किंगडम के लिए आधिकारिक योग मानकों और कार्यक्रमों को लागू करना संभव बना दिया। इन नियमों को लागू करने वाला यह खाड़ी का पहला देश था।
- किंगडम में सबसे बड़ी विदेशी मूल की आबादी लगभग 2.2 मिलियन-मजबूत भारतीय समुदाय है।
- सऊदी अरब और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व वार्षिक हज यात्रा है।

## भारत से अप्रवासी:

- सऊदी अरब में सबसे बड़ी विदेशी मूल की आबादी और "सबसे पसंदीदा समुदाय" 2.6 मिलियन-मजबूत भारतीय समुदाय है। उन्हें विचारशील, अनुशासित, बुद्धिमान और कानून का पालन करने वाला माना जाता है।

## नौसेना प्रशिक्षण:

- अल-मोहद अल-हिंदी ड्रिल, सऊदी अरब और भारत के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, 2021 में आयोजित किया गया था।

## आगे बढ़ने का रास्ता:

- अफगानिस्तान में तालिबान को सीमित करने के लिए सऊदी अरब को पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए राजी करके, भारत अपने लाभ के

लिए सऊदी अरब से अपने करीबी संबंधों का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है।

- दक्षिण पश्चिम एशिया सहयोग से प्रभावित होगा क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।
- स्रोत → हिन्दू



## 2. - बैंकिंग विनियमन अधिनियम:

### GS III

विषय→भारतीय अर्थव्यवस्था

#### ➤ संदर्भ:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वर्तमान में बैंक की वित्तीय स्थिति की सार्वजनिक जांच बढ़ाने के लिए त्रिशूर में निजी बैंक धनलक्ष्मी बैंक पर कड़ी नजर रख रहा है। अधूरे वित्तीय प्रकटीकरण, बढ़ती लागत और सामान्य व्यापार कुप्रबंधन पर अल्पांश शेयरधारकों के एक समूह और बैंक के प्रबंधन के बीच एक लंबी अदालती लड़ाई के जवाब में, आरबीआई ने यह निर्णय दिया। अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने बैंक की बिगड़ती पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के मद्देनजर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विवेकाधीन खर्च शक्ति को प्रतिबंधित करने के बारे में पता लगाने के लिए अगले महीने एक असाधारण आम बैठक आयोजित करने के लिए कहा है।

### बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का वास्तव में क्या अर्थ है?

- 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम एक कानून है। भारतीय बैंक प्रशासन, संचालन और लाइसेंसिंग सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करने के अलावा, यह बैंक गतिविधियों की देखरेख भी करता है। 16 मार्च 1949 को, 1949 का बैंकिंग कंपनी अधिनियम, जिसे स्वीकृत किया गया था, लागू हुआ। 1 मार्च, 1966 को, 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम, जिसे आमतौर पर बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में जाना जाता है, लागू हुआ।

अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं:

- बैंकों को लाइसेंस दिए जाने से पहले, शेयरधारक के स्वामित्व और वोटिंग अधिकारों को विनियमित किया जाना चाहिए।
- बोर्ड और प्रबंधन चयनों की निगरानी करना।
- बैंक संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
- नियंत्रण, विलय, परिसमापन और लेखा परीक्षा के लिए मानक प्रदान करना।

### 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम को संशोधित किया गया है:

- प्रारंभ में, वित्तीय संस्थान बिल के मुख्य लक्ष्य थे। 1965 में जब अधिनियम की धारा 56 जोड़ी गई, तो सहकारी बैंक इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। सहकारी बैंक, जिनके संचालन एक विशेष राज्य तक सीमित हैं, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किए जाते हैं। हालांकि, आरबीआई लाइसेंस देने और कंपनी की गतिविधि की निगरानी करने का प्रभारी है। बैंक अधिनियम पिछले बैंकिंग कानूनों का पूरक था।
- लोकसभा ने हाल ही में 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश को अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका एक ही रुख है और जून 2020 में प्रकाशित हुआ है।
- स्रोत→हिन्दू



## 3. - 5 जी

## ग्लोब इस समय किस राज्य में है?

### GS III

#### विषय→विज्ञान और तकनीक

#### ➤ संदर्भ:

- 5G सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को की थी। श्री मोदी द्वारा भारत में 5G सेवाओं को लॉन्च करने के लगभग तीन सप्ताह बाद, अधिकांश मोबाइल फोन उपयोगकर्ता जिनके पास 5G-सक्षम हैंडसेट है और वे उन क्षेत्रों में हैं जहां सेवाएं दी गई हैं, हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है।

- वाणिज्यिक 5G नेटवर्क 2025 तक 1.1 बिलियन मोबाइल कनेक्शन का समर्थन करने का अनुमान है, जो वैश्विक स्तर पर सभी कनेक्शनों का 12% है, और ऑपरेटरों के लिए US\$1.3 ट्रिलियन तक का राजस्व उत्पन्न करता है। 2020 में, व्यापार के लिए पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया था।
- 50 अमेरिकी शहरों में पहले से ही 5G सेवा है।

## क्या भारत 5G पर स्विच करने में सक्षम है?

- DoT के अनुसार, 13 भारतीय शहरों को 2022 तक 5G सेवा प्राप्त होगी। उनमें से कुछ ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, चंडीगढ़, बंगलोर, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ और गांधीनगर हैं।

#### के बारे में:

- मिलीमीटर-वेव बैंड (30-300 GHz) की वजह से 5G नेटवर्क अविश्वसनीय रूप से तेज़ दरों पर भारी मात्रा में डेटा ले जा सकता है, जिसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है और आसपास के प्रसारणों से न्यूनतम हस्तक्षेप होता है।
- शब्द "5G" मोबाइल ब्रॉडबैंड लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (LTE) नेटवर्क में सबसे वर्तमान प्रगति को दर्शाता है।
- 5G हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में, 20 Gbps इंटरनेट स्पीड (गीगाबिट प्रति सेकंड) का परीक्षण किया गया है।

## 5G के निम्नलिखित लाभ भारत के लिए उपलब्ध हैं:

- नई पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क में भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदलने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ संयुक्त होने पर एक लिंकड और स्वायत्त प्रणाली को एक नया रूप देने की क्षमता है।
- 5G नेटवर्क के परिणामस्वरूप जो लोग बेरोजगार या कम बेरोजगार हैं, उन्हें सार्थक रोजगार मिलने की संभावना दस गुना बढ़ सकती है, जिससे मोबाइल बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।



- व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाकर, भारत सरकार के अधिकारी अत्याधुनिक, बुद्धिमान शहरों का निर्माण करने में सक्षम हैं।
- अधिक विकसित, अधिक डेटा-गहन डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ आने वाली उपयुक्तता और सामाजिक आर्थिक लाभों से लाभ इस प्रकार व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए संभव है।

## 5G की शुरुआत के साथ मुद्दे:

- आवश्यक तत्व 5G को समायोजित करने के लिए संचार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता है। क्योंकि लंबी दूरी पर डेटा भेजना 5G की प्राथमिक कमी है, 5G को समायोजित करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए।
- प्रभावी वित्तीय प्रबंधन रखने वाले 4G से 5G तकनीक पर स्विच करने के लिए, उपभोक्ताओं को नवीनतम सेलुलर तकनीक के उन्नयन के लिए भुगतान करना होगा।
- पूंजी की कमी सक्षम दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा वित्त पोषण प्रदान करने में असमर्थता 5G स्पेक्ट्रम (जैसे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया) के प्रसार में बाधा बन रही है।
- भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में असामयिक रूप से गोद लेने वाले देश 5G तकनीक को धीरे-धीरे अपनाने के परिणामस्वरूप सेवा राजस्व में कमी का अनुभव करेंगे।

## आगे बढ़ना:

- भारत की शीर्ष प्राथमिकताएं अभी 5G रोलआउट के लिए शहरों का चयन कर रही हैं, एक निवेश रणनीति बनाना, अंतिम उपयोगकर्ताओं और आबादी को चुनना, जिन्हें कवर किया जाना चाहिए, वर्तमान नेटवर्क और ऑपरेटरों की पहचान करना, विभिन्न उद्योगों की खपत के आधार पर डिजिटल जोखिम और मूल्य निर्धारण को कम करना, और अंतिम उपयोगकर्ता और जनसंख्या का चयन करना।

- स्रोत → हिन्दू

GURU DEEKSHAA IAS



## 4. - एनजीटी:

### GS II

विषय→सांविधिक और गैर-सांविधिक निकाय

#### ➤ संदर्भ:

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर पखरो टाइगर सफारी परियोजना को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि परियोजना के लिए रिजर्व (एनजीटी) के अंदर पेड़ों को कथित रूप से अवैध रूप से हटाने पर केंद्रीय समिति अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देती।

#### एनजीटी के बारे में:

- यह पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अन्य मुद्दों को जल्दी और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुपालन में स्थापित एक विशेषज्ञ संगठन है।
- एनजीटी को आवेदन या अपील प्राप्त होने के छह महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

#### राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है:

- ट्रिब्यूनल अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों से बना है।
- उनकी पांच साल की नियुक्ति समाप्त होने के बाद वे पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं।

- अध्यक्ष चुनने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत की केंद्र सरकार (CJI) से बात करते हैं।
- राष्ट्रीय सरकार न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों को चुनने के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी।
- दस से बीस पूर्णकालिक न्यायाधीशों और विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

#### निम्नलिखित दीवानी मामलों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा नियंत्रित किया जाता है:

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में पारित किया गया था।
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 में पारित किया गया था।
- वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 का अधिनियम 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम पर आधारित था।
- 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 में पारित किया गया था।
- 2002 का जैविक विविधता अधिनियम

#### राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ओडिशा सरकार और एक स्टील निर्माता पोस्को ने 2012 में एक स्टील परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनजीटी ने शहर के लोगों और जंगलों की सुरक्षा के लिए वीरतापूर्वक कानून का उल्लंघन किया।



- 2013 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को उत्तराखंड बाढ़ मामले में याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया, विशेष रूप से इस स्थिति में "प्रदूषक भुगतान" सिद्धांत पर जोर दिया।
- 2015 एनजीटी के एक आदेश में कहा गया है कि दस साल से पुराने सभी डीजल वाहनों को अब दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं होगी।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक पैनल ने 2017 में यमुना फूड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने का फैसला किया और रुपये का जुर्माना लगाया। 5 करोड़।
- स्रोत→हिन्दू





## संपादकीय विश्लेषण

### 1. तटीय कटाव:

#### पार्श्वभूमि:

- तेज हवाएं, जल निकासी, लहर की क्रिया, लहर धाराएं, और ज्वारीय धाराएं सभी भूमि को दूर करने और समुद्र तट तलछट को हटाकर तटीय क्षरण में योगदान देती हैं। तटीय कटाव और तलछट पुनर्वितरण के अध्ययन को तटीय आकारिकी के रूप में जाना जाता है। इसके कारण जंग, हाइड्रोलिक क्रिया या घर्षण हैं।
- तटीय कटाव को या तो तेजी से शुरू होने वाले या धीमी गति से शुरू होने वाले खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है (कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक होता है) (कई वर्षों में, या दशकों से सदियों तक होता है)।
- भारत में, समुद्र तट और तटरेखा कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें समुद्री वाणिज्य के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य करना, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए स्थान प्रदान करना और मनोरंजन के अवसर प्रदान करना शामिल है।
- हाल के दशकों में तटीय विकास गतिविधियों में वृद्धि हुई है, और इस प्रवृत्ति के जारी रहने की उम्मीद है। किसी भी अन्य समुद्री देश की तरह, भारत का लंबा प्रायद्वीपीय क्षेत्र लगातार क्षरण का सामना कर रहा है।
- तट की गतिशीलता की व्यापक समझ के बिना तटीय विकास परियोजनाएं नियमित रूप से की जाती हैं। स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक नुकसान उठाना पड़ता है, और सबसे खराब स्थिति में, अपरिवर्तनीय क्षति होती है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अनुसार, उच्च, मध्यम और निम्न

तटीय क्षरण भारत के समुद्र तट के 40% हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं।

- विश्लेषण

#### तटीय कटाव को रोकने का क्या महत्व है:

- तटीय क्षेत्र जहां भूमि और जल मिलते हैं, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र की चल रही बातचीत के कारण अत्यंत गतिशील और संवेदनशील हैं।
- इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी मैंग्रोव, जल निकायों, समुद्री शैवाल, प्रवाल भित्तियों, मत्स्य पालन और अन्य समुद्री जीवन के साथ-साथ विभिन्न तटीय और समुद्री वनस्पतियों से बनी है।
- ये पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र को खारे हवाओं, चक्रवातों, सुनामी तरंगों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं, कार्बन पृथक्करण और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, और विनिर्माण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। नतीजतन, तटीय कटाव का मुकाबला करना हमारे लिए एक जोखिम भरा प्रस्ताव है।

#### तटीय कटाव के कारण:

- लहर ऊर्जा को तटीय क्षरण का प्राथमिक कारण माना जाता है।
- महाद्वीपीय ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के जलवायु परिवर्तन-प्रेरित पिघलने से चक्रवात, समुद्री जल थर्मल विस्तार, तूफान की लहरें और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरे बाधित हैं।
- मजबूत तटीय बहाव, जिसके परिणामस्वरूप रेत की आवाजाही होती है, तटीय कटाव के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है।



- ट्रेजिंग, रेत खनन और प्रवाल खनन सभी ने तटीय क्षरण में योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप तलछट की कमी, समुद्र की गहराई में परिवर्तन और लहर का अपवर्तन हुआ है।
- नदी के मुहाने से तलछट के प्रवाह को प्रतिबंधित करके, मछली पकड़ने के बंदरगाह और नदियों और बंदरगाहों के जलग्रहण बेसिन में बने बांधों ने तटीय क्षरण शुरू कर दिया है।
- भारी बारिश मिट्टी की संतृप्ति को बढ़ा सकती है, मिट्टी की कतरनी शक्ति को कम कर सकती है और परिणामस्वरूप ढलान की विफलता (भूस्खलन) का खतरा बढ़ सकता है।

## भारत में तटीय कटाव की स्थिति:

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो भारतीय तट के साथ तटरेखा परिवर्तन की निगरानी करता है, का दावा है कि
- बंगाल की खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा का लगभग 89 प्रतिशत भाग नष्ट कर देती है।
- गोवा में स्थिर तटरेखा का उच्चतम प्रतिशत है।

## दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तटीय क्षरण:

- वैज्ञानिक पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन दुनिया के रेतीले समुद्र तटों के लिए एक संभावित खतरा बन गया है, जिनमें से आधे सदी के अंत तक गायब हो गए हैं।
- विश्लेषण के अनुसार, 2050 तक कुछ तटरेखाओं को पहचाना नहीं जा सकता है, जिनमें से 14 प्रतिशत से 15% तक विनाशकारी क्षरण का खतरा है।
- तमिलनाडु में सबसे हाल की तटरेखा है, जिसके समुद्र तट के 62 प्रतिशत हिस्से में भूमि जुड़ गई है।

## उदाहरण:

- ऐसा लगता है कि सोमेश्वर रुद्रपड़े और उचिला के बीच समुद्र तट का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया गया है
- दूर।
- केरल के तटीय शहरों अलीयारपल्ली, मरक्कादावु, मुर्जिजाड़ी, पुथुपोन्नानी, अझिक्कल, वेलियानकोडे, थन्नीथुरा, पलापेट्टी और कप्पीरक्कड में सैकड़ों लोग समुद्र के कटाव की आशंका के कारण अपने घरों से भाग गए हैं।
- बंगाल की खाड़ी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्षद्वीप द्वीप समूह के समुद्र तटों को शामिल करते हुए भारतीय समुद्र तट लगभग 7517 किलोमीटर तक फैला है।
- भारतीय मुख्य भूमि की 6100 किमी की तटरेखा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई है।
- कांडला, मुंबई, नवाशेवा, मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और पारादीप भारत की लंबी तटरेखा के साथ कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं।

## पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट किस तेजी से खराब हुआ:

- अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी के कठोर जल के कारण भारत के पूर्वी तट में पश्चिमी तट की तुलना में अधिक मिट्टी का क्षरण हुआ।
- क्योंकि पूर्वी तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है, समुद्र वर्ष के अधिकांश समय अशांत रहते हैं।



- पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर से दिसंबर) दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के अलावा पूर्वी तट को प्रभावित करता है, जिससे तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है।
- पश्चिमी तट की तुलना में, जो पिछले तीन दशकों में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, पूर्वी तटरेखा में बंगाल की खाड़ी से आवर्तक चक्रवाती गतिविधि के परिणामस्वरूप कटाव में वृद्धि देखी गई है।

## तटीय कटाव के प्रभावों में शामिल हैं:

### तात्कालिक प्रभाव:

- छोटे द्वीपों को हटाने का काम चल रहा है।
- समुद्र तट तलछट गायब हो रहे हैं।
- तट के साथ मौजूदा वनस्पतियों और जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं।
- समुद्र की दीवारें, रिवेटमेंट, बल्कहेड, और अन्य संरचनाएं जैसे तटीय सुरक्षा खराब हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं।
- कृषि भूमि लुप्त होती जा रही है।
- उत्पादक क्षेत्रों पर तलछट का जमाव।
- घाट खराब हो रहे हैं और ध्वस्त किए जा रहे हैं।
- इमारत की नींव, सीवेज टैंक, पानी की टंकियां और नाव चलाने की सुविधाएं सभी क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं।
- तटरेखा, पुल, सड़क और रेलवे नींव की विफलता ने संचार में बाधा डाली है।

### अन्य प्रभाव:

- जो लोग अपनी आजीविका के लिए तटीय क्षेत्रों पर निर्भर हैं, उन्हें धन की हानि होगी।
- भविष्य के तूफानों के खिलाफ प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की मात्रा कम हो जाएगी।
- अस्थिर चट्टान ढलानों का निर्माण।
- अवरुद्ध सीवर सिस्टम के परिणामस्वरूप समुद्र तट पर प्रदूषण।
- घुटन और खारे पानी का आक्रमण टूटी हुई सुरक्षा के पीछे छिपा है।
- सुरक्षा भंग के परिणामस्वरूप, भूमि क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी।
- पेयजल की कमी नियंत्रण के तरीके

### तटीय कटाव को रोकने के उपाय:

- कठोर-क्षरण नियंत्रण विधियां एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती हैं, जबकि नरम-क्षरण नियंत्रण विधियां एक अस्थायी समाधान प्रदान करती हैं।
- सीवॉल्स और ग्रोइन्स अर्ध-स्थायी बुनियादी ढांचे के उदाहरण हैं। सामान्य टूट-फूट के परिणामस्वरूप, इन इमारतों को पुनर्स्थापित करने या बदलने की आवश्यकता होगी। एक समुद्री दीवार का औसत जीवन काल 50-100 वर्ष है, जबकि एक ग्रोइन का औसत जीवन काल 30-40 वर्ष है। उनके सापेक्ष स्थायित्व के कारण, इन संरचनाओं को क्षरण का अंतिम उत्तर माना जाता है।
- नरम सामग्री के लिए क्षरण नियंत्रण



- अपरदन के प्रभावों को कम करने के लिए शीतल अपरदन रणनीतियाँ अस्थायी समाधान हैं। उदाहरण के लिए, सैंडबैग और समुद्र तट पोषण, दीर्घकालिक या स्थायी समाधान नहीं हैं।
- एक अन्य तकनीक, बीच स्क्रेपिंग या बीच बुलडोजिंग, का उपयोग किसी भवन के सामने एक कृत्रिम टिब्बा बनाने या किसी भवन की नींव की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

करने के लिए सरकार और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना चाहिए।

## स्थानांतरण:

- तट से दूर बुनियादी ढांचे या घरों का स्थानांतरण एक प्रबंधित वापसी के रूप में जाना जाता है। पुनर्निर्माण करते समय पूर्ण और सापेक्ष समुद्र-स्तर वृद्धि और क्षरण दोनों को ध्यान में रखा जाता है।
- तट के पास बड़ी हुई वनस्पतियाँ, जो ढलान की स्थिरता और समुद्र तट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- जियोसिंथेटिक ट्यूबों का उपयोग करना, जो ओडिशा के तट पर पाए जा सकते हैं।
- खाड़ी में बहते रहने के लिए, निचली दीवारों या ग्रेयन्स नामक बाधाओं को समुद्र में डाल दिया जाता है।
- तटीय विकास परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों के स्वदेशी ज्ञान का लाभ उठाना।

## निष्कर्ष:

- नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर) के अनुसार, देश की तटरेखा का लगभग एक तिहाई हिस्सा काफी हद तक खराब हो गया है। हम जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिक तटीय भूमि खो रहे हैं। हमारे तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम



## 2. सभ्यताओं का संघर्ष:

- सभ्यताओं के संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार, शीत युद्ध के बाद की दुनिया में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी।
- अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी. हंटिंगटन के अनुसार, भविष्य के संघर्ष देशों के बजाय संस्कृतियों के बीच छेड़े जाएंगे।
- फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की प्रतिक्रिया में, इसे शुरू में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में 1992 के भाषण में दिया गया था, और बाद में 1993 में "द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन" नामक विदेशी मामलों के टुकड़े में इसका विस्तार किया गया। हंटिंगटन ने 1996 में प्रकाशित द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में अपने विचारों का विस्तार किया।
- 1946 में अल्बर्ट कैमस द्वारा अभिव्यक्ति को लोकप्रिय बनाया गया था, [9] 1988 में अयोध्या विवाद के अपने अध्ययन में गिरिलाल जैन, द अटलांटिक मंथली के सितंबर 1990 के अंक में बर्नार्ड लुईस ने अपने लेख "द रूट्स ऑफ मुस्लिम रेज" में, और महदी एल मांडजरा में 1992 में उनकी पुस्तक "ला प्रीमियर कॉम्बैट सिविलाइजेशननेल"।
- वाक्यांश "यंग इस्लाम ऑन ट्रेक: ए स्टडी इन सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट" पहली बार 1926 में बेसिल मैथ्यूज द्वारा लिखित मध्य पूर्व के बारे में एक पुस्तक में दिखाई देता है।
- हंटिंगटन ने शीत युद्ध के बाद के युग में विश्व राजनीति की प्रकृति पर विभिन्न दृष्टिकोणों को देखकर अपनी जांच शुरू की। कुछ दार्शनिकों और लेखकों के अनुसार, मानवाधिकार, उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, शीत युद्ध के बाद की दुनिया में राज्यों के लिए एकमात्र शेष वैचारिक विकल्प बन गए हैं। हेगेलियन अर्थ में, फ्रांसिस फुकुयामा ने दावा किया कि दुनिया "इतिहास के अंत" तक पहुंच गई है।
- जबकि विचारधारा का युग बीत चुका था, हंटिंगटन ने कहा कि दुनिया सांस्कृतिक संघर्ष द्वारा चिह्नित मामलों की प्राकृतिक स्थिति में वापस आ गई है।
- अपनी थीसिस में, उन्होंने अनुमान लगाया कि भविष्य में संघर्ष की प्रमुख धुरी सांस्कृतिक होगी।
- हंटिंगटन भी सभ्यताओं के संघर्ष को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखता है।
- विश्व इतिहास में शासकों, सरकारों और आदर्शों के बीच संघर्षों का बोलबाला हुआ करता था, जैसे कि पश्चिमी सभ्यता में पाए जाने वाले।
- शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, हालांकि, विश्व राजनीति ने एक नए युग में प्रवेश किया, जिसमें गैर-पश्चिमी सभ्यताएं अब पश्चिमी सभ्यता के शोषित लाभार्थी नहीं थीं, बल्कि इसके बजाय पश्चिम के साथ-साथ विश्व इतिहास को आकार देने और प्रगति करने में अभिन्न खिलाड़ी थे।

**Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are**



**Vijay Kumar G**

*Founder and Director*  
**Guru Deekshaa IAS**

- ✍ First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- ✍ Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- ✍ Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

**CALL US FOR MORE DETAILS**

**☎ 76 76 74 98 77**

**JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES**

 **@GURU\_DEEKSHAAIAS**



**FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES**

 **GURUDEEKSHAA**

